चुनाव में स्वास्थ्य व शिक्षा पर सार्थक बहस ज़रूरी

भारत डोगरा

लोकतंत्र में चुनाव अभियान केवल सत्ता के लिए संघर्ष नहीं होते, उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक जन-विमर्श का स्थान भी बनना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो मौजूदा चुनाव अभियान में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। घोषणा पत्रों में चाहे ये विषय मुद्दों के रूप में मौजूद हैं, किंतु इन पर कोई व्यापक या सार्थक बहस नहीं हो सकी है।

अच्छे स्वास्थ्य का आधार अच्छे पोषण व अन्य बुनियादी ज़रूरतों की आपूर्ति से बनता है। सभी को ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं, दवाएं व जांच उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध होना चाहिए, जो जीडीपी के 4 या 5 प्रतिशत के आसपास हो सकता है। साथ में स्वास्थ्य क्षेत्र में मुनाफखोरी पर सख्ती से नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। दवा नीति में बदलाव करके दवाइयों की उपलब्धता और कीमतों को वास्तविक ज़रूरतों के अनुकूल बनाना चाहिए जिससे अनावश्यक व हानिकारक दवाइयों पर रोक लगे व ज़रूरी दवाइयां न्यायसंगत कीमत पर उपलब्ध हो सकें। जेनेरिक दवाइयों को प्रोत्साहित करना चाहिए। वैक्सीन नीति में ज़रूरी बदलाव होने चाहिए ताकि ज़रूरी वैक्सीन की कमी न हो व संदिग्ध उपयोगिता के (या संभावित जोखिम वाले) वैक्सीन से बचा जा सके। स्वास्थ्य सेवाओं, जांच व दवाइयों की उपलब्धता के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों व निर्धन वर्ग को विशेष महत्व मिलना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन, साफ पेयजल व बुनियादी ज़रूरतों की आपूर्त्ति ज़रूरी है। अतः इस बुनियाद को मज़बूत करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

गांवों में डॉक्टरों व पैरा-मेडिकल स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल शिक्षा में जरूरी सुधार करने चाहिए।

तरह-तरह की महंगी व विसंगतिपूर्ण योजनाओं पर पुनर्विचार करके समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की ओर बढ़ना चाहिए।

देशी चिकित्सा पद्धतियों को समुचित महत्व देते हुए इनके वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए और इन्हें मुनाफाखोरी से बचाना चाहिए।

सेवाभाव से आगे आने वाले डॉक्टरों, विशेषकर युवाओं को सरकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

सरकार को स्वास्थ्य व औषधि क्षेत्र में मुख्य ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हुए निजीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तेज़ प्रसार व उन पर निर्भरता की प्रवृति को रोकना चाहिए। पेटेंट कानूनों या अन्य तरीकों से मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए।

बाल व मातृ मृत्यु दर कम करने के अभियान को उच्च प्राथमिकता देते हुए जन भागीदारी से चलना चाहिए।

सब तक शिक्षा पहुंचाने के लक्ष्य व अधिकार को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा का बजट जीडीपी के 6 से 7 प्रतिशत तक करना चाहिए पर साथ में शिक्षा में मुनाफाखोरी व निजीकरण की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। सरकारी स्कूलों की शिक्षा सुधारने को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। दूर-दूर के गांवों में शिक्षा से कोई वंचित न हो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी हो तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज़रूरतमंद बच्चों हेतु विशेष शालाओं व ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जा सकती है।

शिक्षा में सांप्रदायिकता के प्रवेश पर पूरी रोक लगनी चाहिए। शिक्षा में इंसानियत के मुख्य संदेश, सब इंसानों की बराबरी और उनमें आपसी सद्भाव, सहयोग का संदेश धर्म निरपेक्ष ढंग से दिया जाना चाहिए। इसी तरह नैतिकता के अन्य गुणों का समावेश शिक्षा में होना चाहिए जिनमें ईमानदारी, सेवा, करुणा, मेहनत जैसे शाश्वत व सर्वमान्य गुणों को विशेष महत्व देना चाहिए। स्पर्धा के स्थान पर आपसी सहयोग को महत्व मिलना चाहिए।

उच्च शिक्षा को देश की ज़रूरतों के नज़दीक लाना चाहिए व साथ में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धन वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के अच्छे अवसर मिल सकें।

शिक्षा में निजीकरण व मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना चाहिए।

शिक्षा देश के मेहनतकश वर्ग से जोड़ने वाली होनी चाहिए व समाज सेवा से जोड़ने वाली होनी चाहिए।

बाल श्रम व बच्चों के हर तरह के शोषण पर रोक लगनी चाहिए। अपने परिवार व पड़ौस में हुनर व कौशल सीखने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। बच्चों की ट्रैफिकिंग रोकने के अधिकतम प्रयास होने चाहिए। गुमशुदा बच्चों को खोजने और परिवार को लौटाने की व्यवस्था को सुधारना ज़रूरी है।

बालिकाओं की शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बेघर, अनाथ व अन्य कठिन परिस्थितियों को झेल रहे बच्चों के कार्यक्रमों में व्यापक सुधार होने चाहिए।

युवाओं के सामने समाज की बेहतरी से जुड़े रोज़गार व स्व रोज़गार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए व उन्हें इनकी पर्याप्त जानकारी मिलनी चाहिए। युवाओं की रचनात्मकता को विविध क्षेत्रों में खिलने के समुचित अवसर मिलने चाहिए। उच्च शिक्षा को देश की वास्तविक ज़रूरतों से जोड़ना चाहिए और इसके लिए उपलब्ध सीमित संसाधनों का उपयोग सावधानी से होना चाहिए। ***(स्रोत फीचर्स)***